



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 315]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 01, 2019/आश्विन 9, 1941

No. 315]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 01, 2019/ASVINA 9, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2019

(द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच)

मामला सं. (एसजी) 08/2019

विषय: भारत, कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय) नियम, 2017 के अधीन कोरिया से भारत में "थेलेटिक एनहाइड्राइड" के आयातों के संबंध में द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच की शुरुआत की सूचना।

फा. सं. 22/8/2019-डीजीटीआर.—यतः मै. आई जी पैट्रोकेमिकल्स लि. और मै. थिरूमलाई कैमिकल्स लिमिटेड (जिन्हें आगे आवेदक कहा गया है) द्वारा भारत, कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय) नियम, 2017 (जिसे आगे उक्त नियम भी कहा गया है) के अधीन एक आवेदक प्रस्तुत किया है जिसमें कोरिया गणराज्य (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) से थेलेटिक एनहाइड्राइड (जिसे आगे विचाराधीन उत्पाद या पीयूसी या संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के बड़े हुए आयातों, जिस कारण भारत में समान या सीधे प्रतिस्पर्धी उत्पाद के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हो रही है, का आरोप लगाया गया है।

विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

- वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "थेलेटिक एनहाइड्राइड" है, जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के एच एस कोड 19173500 के अधीन आता है। यह एक रंगहीन, ठोस होता है जिसे विभिन्न रूप में थेलेटिक एनहाइड्राइड फ्लेक, थेलेटिक एनहाइड्राइड (98 प्रतिशत न्यूनतम) थेलेटिक एसिड एनहाइड्राइड, थेलेटिक एनहाइड्राइड (99.8 प्रतिशत न्यूनतम) आदि बताया जाता है।

घरेलू उद्योग

3. यह आवेदन मै. आई जी पेट्रोकेमिकल्स लि. और मै. थिरूमलाई केमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों का भारत में समान घरेलू वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है और इसलिए आवेदक नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग हैं।

जांच अवधि

4. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचारित अवधि अप्रैल, 15 से जून, 19 तक की है। आवेदकों ने 18-19 की चौथी तिमाही और 19-20 की पहली तिमाही में आयातों में अचानक वृद्धि का दावा किया है।

संबद्ध देश

5. वर्तमान जांच में शामिल देश कोरिया गणराज्य है।

बढ़े हुए आयात

6. आवेदकों ने दावा किया है कि कोरिया गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में समग्र रूप से और भारत में उत्पादन तथा खपत के संबंध में वृद्धि हुई है। यह नोट किया जाता है कि पीयूसी के आयातों में 2018-2019 की चौथी तिमाही और 2019-20 की पहली तिमाही के दौरान अचानक, तीव्र और भारी वृद्धि हुई है। संबद्ध वस्तु के आयातों में वृद्धि की दर को अवधि, मात्रा और भारत में कुल आयात तथा खपत पर विचार करते हुए काफी अधिक माना गया है।

घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति

7. आवेदकों ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के बढ़े हुए उत्पादों से 2018-2019 की चौथी तिमाही और 2019-20 की पहली तिमाही के दौरान घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हुई है और गंभीर क्षति का खतरा भी है। आवेदकों ने उत्पादन, उत्पाद की बिक्री और क्षमता उपयोग में गिरावट का दावा किया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है और आयातों का बाजार हिस्सा बढ़ा है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उनके लाभ, नकद लाभ, पी बी आई टी, आर आ आई और लाभप्रदता में गिरावट आई है।
8. आवेदकों ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों में भारी वृद्धि के कारण द्विपक्षीय रक्षोपाय शुल्क को तत्काल लगाने का अनुरोध किया है।
9. प्राधिकारी पाते हैं कि इस बात के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों में भारी वृद्धि हुई है जिससे भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हुई है और संबद्ध देश से बढ़े हुए आयातों और घरेलू उद्योग को हुई गंभीर क्षति के बीच कारणात्मक संबंध है।

जांच शुरूआत

10. यह निर्धारित करने के बाद कि रक्षोपाय जांच की शुरूआत को न्यायोचित बनाने के लिए पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं, महानिदेशक जांच की शुरूआत करना उचित समझते हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या कोरिया गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के आयात बढ़े हुए आयात माने जा सकते हैं या क्या बढ़े हुए आयात हुए हैं या उनसे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होने का खतरा है।
11. सभी हितबद्ध पक्षकार इस सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत करा सकते हैं:

महानिदेशक
व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर)
जीवन तारा बिल्डिंग, चौथा तल,
5 संसद मार्ग,
नई दिल्ली 110001

12. सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को अलग से भी लिखा जा रहा है।
13. जांच से संबंधित कोई भी अन्य पक्षकार जो हितबद्ध पक्षकार माना जाना चाहता हो, अपना अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है जो इस सूचना की तारीख से 30 दिन के भीतर उपर्युक्त पते पर महानिदेशक को पहुँच जाए।
14. यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो महानिदेशक रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं। सूचना हार्ड कॉपी तथा सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत की जानी चाहिए।
15. **गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना** – प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (परिशिष्टों/उससे संलग्न अनुलग्नक सहित), प्रश्नावली के उत्तर सहित प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से अपेक्षा है कि वे उन्हें दो अलग-अलग सेटों में, यदि उसके किसी भाग में "गोपनीयता" का दावा किया गया है, दायर करें। "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। इस प्रकार की मार्किंग के बिना किया गया कोई भी अनुरोध महानिदेशक द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और महानिदेशक उन अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों रुपांतरों की सॉफ्ट प्रतियां भी प्रत्येक के दो (2) सेटों में हार्ड प्रतियों के साथ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा। गोपनीय रुपांतर में वह सभी सूचना होगी जो प्रकृति में गोपनीय हैं और/अथवा अन्य सूचना होगी जो उस सूचना को देने वाला गोपनीय होने का दावा करता है, जिस सूचना को प्रकृति में गोपनीय होने का दावा किया जाए अथवा जिस सूचना के संबंध में अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, सूचना देने वाले से यह अपेक्षा है कि वे दी गई सूचना के साथ उसका सही कारण का विवरण दें कि उस सूचना को प्रकट क्यों नहीं किया जा सकता। अगोपनीय रुपांतर में गोपनीय सूचना के साथ, अधिमानतः सूचीबद्ध अथवा खाली रखा गया (यदि सूचीकरण व्यवहार्य नहीं है) और जिस सूचना के संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है, उस पर आधारित सार का प्रदर्शन होना अपेक्षित है। अगोपनीय सार में गोपनीय आधार पर दी गई सूचना के सार को उपयुक्त रूप से समझने के लिए पर्याप्त व्यौरा होने चाहिए। तथापि, अपवादस्वरूप परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि वह सूचना सार में अतिसंवेदनशील नहीं है और कारणों का यह विवरण कि उसका सार करना क्यों संभव नहीं है, महानिदेशक की संतुष्टि के अनुसार दिया जाना चाहिए। महानिदेशक प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के लिए अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि महानिदेशक संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है और यदि सूचना देने वाला सूचना को सार्वजनिक करने का इच्छुक नहीं है अथवा उसे सामान्यीकृत अथवा सार रूप में प्रकट करने के लिए प्राधिकृत करता है, तो वे उस सूचना को अनदेखा कर सकते हैं। कोई भी अनुरोध, जो उसके सार्थक अगोपनीय रुपांतर के बिना किया गया है अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में सही कारणों के विवरण के बिना किया गया है, महानिदेशक द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा। महानिदेशक संतुष्ट होने पर तथा दी गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता स्वीकार करने पर उसे सूचना देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को प्रकट नहीं करेंगे।
16. कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रुपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।
17. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उपयुक्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है अथवा अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में पर्याप्त व्यवधान डालता है तो महानिदेशक उनके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं और केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिश कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the, 1st October, 2019

(Bilateral Safeguard Investigation)

Case No. (SG) 08/2019

Subject: Initiation of Bilateral Safeguard Investigation concerning imports of “Phthalic Anhydride” into India from Korea RP under India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017

F. No. 22/8/2019-DGTR.—Whereas, an application has been filed under India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 (hereinafter also referred to as the “said Rules”) by M/s. I G Petrochemicals Limited and M/s Thirumalai Chemicals Ltd., (hereinafter also referred to as the “Applicants”) alleging increased imports of “Phthalic Anhydride” (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or “PUC” or subject goods) from Korea RP (also referred to as subject country) causing serious injury to the domestic producers of like or directly competitive product in India.

Product under Consideration (PUC)

2. The product under consideration in the present investigation is “Phthalic Anhydride, falling under the HS code 29173500 of the Customs Tariff Act, 1975. It is a colourless solid, variously referred as Phthalic Anhydride flakes, Phthalic Anhydride (98% min.), Phthalic Acid Anhydrous, Phthalic Anhydride (99.8% min) etc.

Domestic Industry

3. The application has been filed by M/s. I G Petrochemicals Limited and M/s. Thirumalai Chemicals Ltd. The applicants account for a major share of the total Indian production of the domestic like goods in India and thus applicants constitute Domestic Industry as per the Rules.

Period of Investigation

4. The period considered for the purposes of present investigation is from April, 2015 to June 2019. The applicants have claimed surge in imports in Q4 18-19 and Q1 19-20.

Subject country

5. The country involved in the present investigation is Korea RP.

Increased Imports

6. The applicants have claimed that imports of product under consideration from Korea RP have increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India. It is noted that there is a sudden, sharp and significant increase in imports of PUC during Q4 of 2018-19 and Q1 2019-20. The rate of increase in imports of subject goods is considered significant considering the duration, the quantum, the total imports and the consumption in India.

Serious Injury to the domestic industry

7. The applicants have claimed that the increased imports of product under consideration has caused and is also threatening to cause serious injury to the domestic producers during Q4 of 2018-19 and Q1 2019-20. The applicants have claimed decline in production, sales and capacity utilization for the product. They have also claimed that market share of domestic industry has declined whereas market share of subject imports has increased. They have also claimed that their profits, cash profits, PBIT, ROI and productivity have declined.
8. The applicants have requested for immediate imposition of bilateral safeguard duty in view of significant increase in imports of subject goods from subject country.
9. The Authority finds that there is prima facie evidence that imports of product under consideration have increased significantly causing serious injury to the domestic producers of the like article in India and there is causal link between increased imports from subject country and the serious injury caused to the domestic industry.

Initiation

10. After determining that there is prima facie evidence to justify initiation of the safeguard investigation, the Director General considers appropriate to initiate the investigation in order to determine whether the imports of the product under consideration from Korea RP constitute increased imports and whether the increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to the domestic industry.
11. All interested parties may make their views known within a period of 30 days from the date of this notice to:

Director General

Directorate General of Trade Remedies (DGTR),

Jeevan Tara Building, 4th Floor

5, Parliament Street,

New Delhi -110001

12. All known interested parties are also being addressed separately.
13. Any other party to the investigation who wishes to be considered as an interested party may submit its request so as to reach the Director General on aforementioned address within 30 days from the date of this notice.
14. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Director General may record its findings on the basis of the facts available on record. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.
15. Submission of Information on Confidential Basis – The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non- confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Director General and the Director General shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in two (2) sets of each. The confidential version shall contain all information which are by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. The information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Director General. The Director General may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Director General is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information. Any submission made without a meaningful non- confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Director General. The Director General, on being satisfied and accepting the need for keeping the information provided as confidential shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.
16. Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidences submitted by other interested parties.
17. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Director General may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority